सभी देशों को रूसी तेल खरीदने अमेरिका ने दी अनुमति

ईरान ने कीमतें 200 डॉलर तक पहुंचने की चेतावनी दी, होर्मुज स्ट्रीट बंद होने से बढ़ा ऊर्जा संकट

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें तेजी से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने अस्थायी कदम उठाते हुए अन्य देशों को रूस से कच्चा तेल खरीदने की सीमित अनुमति दे दी है। यह छूट 30 दिनों के लिए दी गई है, ताकि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ाई जा सके और कीमतों में तेजी को रोका जा सके।

भारत में तेल-गैस होर्मुज स्ट्रीट से आता है

विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है। भारत सहित कई देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते से प्राप्त करता है, जबकि देश की तरलीकृत प्राकृतिक गैस का भी बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है। इस बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध की स्थिति और बिगड़ती है तथा तेल आपूर्ति लंबे समय तक प्रभावित रहती है, तो कच्चे तेल की कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं।उल्लेखनीय है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाए थे। उस समय पश्चिमी देशों का मानना था कि रूस को युद्ध के लिए आर्थिक संसाधन तेल और गैस की बिक्री से मिल रहे हैं। इसी कारण रूसी ऊर्जा व्यापार को सीमित करने के लिए कई आर्थिक प्रतिबंध लागू किए गए थे। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के कारण अमेरिका को अस्थायी रूप से यह राहत देने का निर्णय लेना पड़ा है, ताकि बाजार में आपूर्ति बनी रहे और कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी को रोका जा सके।

छूट 11 अप्रैल तक

अमेरिकी प्रशासन के इस निर्णय के तहत उन रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति की अनुमति दी गई है, जो 12 मार्च की रात 12 बजकर 1 मिनट से पहले जहाजों पर लोड किए जा चुके थे। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में एक विशेष लाइसेंस जारी किया है। इसके अनुसार यह छूट केवल 11 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।

अल्पकालिक व्यवस्था

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि यह केवल अल्पकालिक व्यवस्था है और इससे रूस को कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है। उनके अनुसार रूस की आय का बड़ा हिस्सा तेल उत्पादन के दौरान लगाए जाने वाले करों से आता है, जबकि यह छूट केवल उस तेल के लिए दी गई है जो पहले से ही समुद्री मार्ग में है।

होर्मुज स्ट्रीट बंद

दरअसल, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रीट से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

मासिक धर्म अवकाश पर याचिका खारिज

कानून बना तो महिलाओं के रोजगार और करियर पर पड़ सकता है असरः सर्वोच्च न्यायालय

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान सवेतन अवकाश देने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी याचिकाएं अनजाने में महिलाओं के बारे में बनी रूढ़ धारणाओं को और मजबूत कर सकती हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि इस संबंध में कानून बनाया जाता है तो इसका महिलाओं के रोजगार और करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यदि निजी क्षेत्र में हर महीने एक दिन अनिवार्य अवकाश का प्रावधान किया गया तो नियोक्ता महिलाओं को जिम्मेदारियां देने से बच सकते हैं। इससे महिलाओं के पेशेवर विकास पर भी नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है।

अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी याचिकाएं कभी-कभी यह संदेश देती हैं कि मासिक धर्म महिलाओं के लिए कोई नकारात्मक स्थिति है, जबकि यह उनका स्वाभाविक और सकारात्मक अधिकार है। अदालत ने कार्यस्थलों पर बनने वाली मानसिकता को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस विषय पर स्वयं किसी महिला ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है।

याचिकाकर्ता शैलेंद्र मणि इस मुद्दे को लेकर तीसरी बार सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे। इससे पहले फरवरी 2023 में अदालत ने उन्हें अपना पक्ष केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष रखने की अनुमति दी थी। इसके बाद 2024 में दायर याचिका में केंद्र सरकार से इस विषय पर नीतिगत निर्णय लेने पर विचार करने को कहा गया था।

नवीन याचिका में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मासिक धर्म से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को मान्यता देते हुए महिलाओं को अवकाश सहित आवश्यक राहत देने के लिए नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

भारतीय मूल के दो भाइयों को 835 वर्ष की सजा

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिका में भारतीय मूल के दो भाइयों को बड़े चिकित्सा घोटाले और वीजा से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया है। पेनसिल्वेनिया में रहने वाले भास्कर सवानी और अरुण सवानी को अदालत ने अधिकतम 835 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई है। मामले में उनकी सहयोगी अलेक्जेंड्रा ओला राडोमिक को भी दोषी पाया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार दोनों भाइयों ने लगभग दस वर्षों तक कंपनियों और दंत चिकित्सा केंद्रों का जाल बनाकर व्यापक स्तर पर धोखाधड़ी की। आरोप है कि उन्होंने चिकित्सा सहायता योजना मेडिकेड से लगभग तीन करोड़ डॉलर, यानी करीब 250 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की। जांच में यह भी सामने आया कि कई ऐसे उपचारों के बिल लगाए गए जो वास्तव में किए ही नहीं गए थे। इसके अलावा बिना अनुमति के दंत प्रत्यारोपण किए जाने के आरोप भी लगे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपियों ने एच-1बी वीजा के माध्यम से विदेशों, विशेष रूप से भारत से कर्मचारियों को बुलाने के लिए फर्जी आवेदन किए और वेतन का हिस्सा वापस लौटाने का दबाव भी डाला।

सड़कों, पुलों और बिजली तारों की देखभाल वाली याचिका अस्वीकार

क्या आप चाहते हैं न्यायालय पूरे देश को चलाएः सुप्रीम कोर्ट

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें देशभर की सड़कों, पुलों और बिजली की तारों जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की नियमित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि यह याचिका शॉपिंग मॉल जैसी है, जिसमें हर तरह की मांग रख दी गई है। पीठ ने बताया कि इतने व्यापक आदेश देना असंभव है, जब तक मुद्दे स्पष्ट और विशेष न हों। याचिकाकर्ता उचित प्रक्रिया अपनाकर संबंधित उच्च न्यायालय में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि सरकारी लापरवाही के कारण देशभर में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वे सड़कों, पुलों और बिजली तारों की नियमित जांच और मरम्मत करें, उच्च स्तरीय स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट समिति बनाएं, जिसमें सिविल इंजीनियर, इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ, फोरेंसिक जांचकर्ता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हों।

एच-1बी वीजा प्रक्रिया अमेरिका ने बदली

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः अमेरिका ने एच-1बी वीजा देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए चयन प्रणाली को वेतन आधारित बना दिया है। अब लाभार्थियों का चयन पहले की तरह यादृच्छिक लॉटरी से नहीं होगा, बल्कि आवेदकों के वेतन स्तर के आधार पर किया जाएगा। अमेरिकी आव्रजन एजेंसी ने इसके लिए प्रपत्र आई-129 का नया स्वरूप तैयार किया है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों के लिए दायर याचिका में नौकरी से जुड़ी विस्तृत जानकारी देनी होगी। इससे अधिक अनुभव और अधिक वेतन पाने वाले पेशेवरों को वीजा मिलने की संभावना पहले की तुलना में अधिक हो जाएगी। नई प्रणाली में आवेदकों को चार वेतन स्तरों में विभाजित किया जाएगा। जिस पद का वेतन स्तर जितना अधिक होगा, चयन प्रक्रिया में उसे उतने अधिक अवसर मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर चौथे स्तर के उम्मीदवार को चार अवसर मिलेंगे, जबकि पहले स्तर के उम्मीदवार को केवल एक अवसर मिलेगा।

प्रपत्र आई-129 का उपयोग अस्थायी कामगारों को अमेरिका बुलाने के लिए किया जाता है। अमेरिकी श्रम विभाग प्रत्येक पेशे और शहर के लिए एक मानक वेतन निर्धारित करता है, जिसके आधार पर नौकरियों को पहले स्तर से चौथे स्तर तक वर्गीकृत किया जाता है। सबसे अधिक प्रभाव भारतीय पेशेवरों पर पड़ सकता है, क्योंकि हर वर्ष एच-1बी वीजा 70 प्रतिशत भारतीयों को मिलते हैं। भारत से बड़ी संख्या में अभियंता और संगणक विज्ञान के स्नातक अमेरिका की तकनीकी उद्योग में कार्य करते हैं। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट और एचसीएल जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए सबसे अधिक एच-1बी वीजा प्रायोजित करती हैं।

अफगानिस्तान का पाक पर जवाबी हमला

खैबर पख्तूनख्वा के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

इस्लामाबाद, एजेंसीः अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अफगान वायुसेना ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया। मंत्रालय के अनुसार यह कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा एक दिन पहले अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है। रक्षा मंत्रालय ने सामाजिक माध्यम पर जारी बयान में बताया कि कोहाट क्षेत्र में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और एक सैन्य किले को निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले में किसी के मारे जाने या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और कंधार सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई हमले किए थे। तालिबान प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। हमलों में कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने एक निजी विमानन कंपनी के ईंधन भंडार को भी निशाना बनाया, जहां से नागरिक विमानों और संयुक्त राष्ट्र के विमानों को ईंधन की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार की कार्रवाई का उचित जवाब दिया जाएगा।

वहीं पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों के खिलाफ की गई थी। उनका दावा है कि हाल के महीनों में बढ़ते आतंकी हमलों के कारण यह अभियान चलाया गया है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव फरवरी के अंत से बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में बार-बार हमले और जवाबी कार्रवाई के कारण हालात युद्ध जैसे बनते जा रहे हैं।

पेज एक से जारी खबरों के शेष...

भारत हमारा दोस्त, होर्मुज में ...

जर्मनी युद्ध का हिस्सा नहीं : इसी दौरान जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने स्पष्ट किया कि उनका देश ईरान से जुड़े युद्ध का हिस्सा नहीं है और न ही बनने की इच्छा रखता है। नॉर्वे की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई कारण नहीं है कि जर्मनी होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को सैन्य सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करे।

170 भारतीय नागरिक आर्मेनिया पहुंचे : भारत सरकार ने बताया कि ईरान में फंसे लगभग 170 भारतीय नागरिक जमीन के रास्ते आर्मेनिया पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार इनमें से कुछ लोग भारत लौट चुके हैं, जबकि बाकी नागरिक आने वाले दिनों में वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से वापस लाए जाएंगे। भारत सरकार ने ईरानी नेतृत्व के साथ बातचीत में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है।

युद्धविराम की अपील : संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इजराइल और हिजबुल्लाह से तत्काल युद्धविराम की अपील की है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को संघर्ष समाप्त कर क्षेत्र में शांति बहाल करनी चाहिए।

डबल इंजन सरकार बहनों का...

मुख्यमंत्री ने ग्वालियर जिले को लगभग 122 करोड़ रुपए लागत के 54 विकास कार्यों की सौगात भी दी। इनमें करीब 60 करोड़ रुपए के 35 कार्यों का भूमिपूजन और लगभग 62 करोड़ रुपए के 19 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। कुलैथ घाटीगांव में लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से बने शासकीय सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने भितरवार क्षेत्र में 120 करोड़ रुपए लागत की आरोन-पटई उद्वहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। साथ ही भितरवार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नत कर सिविल अस्पताल बनाने तथा घाटीगांव के उप स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन की घोषणा की। भितरवार और घाटीगांव में युवाओं के कौशल विकास के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि घाटीगांव में शबरी माता धाम और भगवान देवनारायण धाम का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा घाटीगांव, चिनौर और करैया में सांदीपनि विद्यालय खोले जाएंगे।

देश तेजी से विकास कर रहा: सिंधिया

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के बिना विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित अनेक जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

आरएसएस की अखिल भारतीय...

अगले दो साल में नौ राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू और केरल के चुनाव इस वर्ष महत्वपूर्ण होंगे, जबकि उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव 2027 में होंगे। संघ समाज में संपर्क बढ़ाने, अनुसूचित समाज और संत रविदास जयंती के कार्यक्रमों पर भी ध्यान देगा। सभा के अंतिम दिन 15 मार्च को मोहन भागवत का संबोधन होगा। इसके बाद दत्तात्रेय होसबाले द्वारा सभा में लिए गए निर्णय और पारित प्रस्तावों की आधिकारिक जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाएगी। इस बैठक में संघ का शताब्दी वर्ष और देशभर में अब तक 10 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच सहित विभिन्न कार्यक्रमों पर विशेष चर्चा होगी।

स्पेशल खबर ओडिशा और हरियाणा के विधायकों को सुरक्षित रिसॉर्ट में रखा...

राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सुरक्षा सतर्कता

हॉर्स ट्रेडिंग का डरः विधायकों को अलग-अलग स्थानों पर भेजा गया

भुवनेश्वर/बेंगलुरु/चंडीगढ़, एजेंसीः राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सताने लगा है। इसी वजह से पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए ओडिशा और हरियाणा में रिजॉर्ट और अन्य गोपनीय स्थानों पर भेजा है। ओडिशा कांग्रेस के आठ विधायक दक्षिण बेंगलुरु के वंडरला रिजॉर्ट में ठहरे हैं। इनमें अशोक कुमार दास, प्रफुल्ल चंद्र प्रधान, पवित्र सांता, कद्रका अप्पाला स्वामी, सी.एस. राजन एक्का और सत्यजीत गोमांगो शामिल हैं। इनमें से चार विधायक विधानसभा के बजट सत्र में भुवनेश्वर में ही मौजूद हैं। शनिवार तक चार और विधायक बेंगलुरु पहुंच सकते हैं। ओडिशा में कुल 12 कांग्रेस विधायक हैं। कांग्रेस ने बीजू जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सहयोग से दत्तेश्वर होता को समर्थन देने का फैसला किया है। अप्रैल में ओडिशा से चार राज्यसभा सीटें खाली होंगी और कुल पांच उम्मीदवार मैदान में हैं।

हरियाणा में भी सुरक्षा व्यवस्था की गई। दो राज्यसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने सभी 37 विधायकों को हिमाचल प्रदेश भेजने की तैयारी की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों को लंच पर बुलाया और 5 जोड़ी कपड़े साथ लाने के निर्देश दिए। विधायकों को गोपनीय और सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए हिमाचल सरकार से सहयोग लिया गया। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा की दो सीटों के लिए भाजपा ने संजय भाटिया और कांग्रेस ने कर्मवीर बौद्ध को प्रत्याशी बनाया है। निर्दलीय सतीश नांदल मैदान में हैं। कांग्रेस को डर है कि यदि कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करें तो निर्दलीय उम्मीदवार जीत सकते हैं। इस स्थिति में कांग्रेस ने विधायकों की निगरानी और सुरक्षित स्थानों पर उनकी तैनाती कर अपने पक्ष को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है।